

## अमेरिका-सऊदी समझौता

द हिन्दू

पेपर- II ( अन्तर्राष्ट्रीय संबंध )

संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब के बीच आठ दशकों से भी अधिक समय से चले आ रहे संबंधों में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं - 1973 के तेल प्रतिबंध से लेकर 2018 में जमाल खशोगी की हत्या तक। हालांकि, इस रिश्ते की दो तस्वीरें प्रतिष्ठित बनी हुई हैं: पहली तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट और सऊदी अरब के राजा अब्दुल अजीज अल-सऊद के बीच वेलेंटाइन डे 1945 को एक अमेरिकी क्रूजर पर हुई मुलाकात की है, जो सात दशकों के अटूट द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत है। इसे एक कम प्रचारित लेकिन मौलिक खेल-से-सुरक्षा सहजीवन द्वारा रेखांकित किया गया था। दूसरी प्रतिष्ठित तस्वीर 15 जुलाई, 2022 को रियाद में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) के बीच मुट्ठी बांधने की है, जो अधिक समान और बड़े पैमाने पर लेन-देन वाली साझेदारी का प्रतीक है।

बारे में चर्चा की जाए तो रियाद और वाशिंगटन एक नए और बेहतर रिश्ते की कगार पर हैं, जिसे अस्थायी रूप से रणनीतिक गठबंधन समझौता (एसएए) नाम दिया गया है। पिछले एक साल से उनके बीच चल रही इस शबड़ी सौदेबाजी को एमबीएस के नेतृत्व में अल-सऊद की घरेलू और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के साथ व्हाइट हाउस की उत्सुकता के साथ मेल खाने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि श्री बिडेन के फिर से चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की जा सके।

### समझौते की परतें:

अमेरिकी मीडिया के एपिसोडिक कवरेज के बीच की पक्तियों को पढ़ते हुए, <sup>1</sup> के तीन परस्पर जुड़े हुए घटक हो सकते हैं: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक। द्विपक्षीय स्तर पर, यह मौजूदा अंतर्निहित द्विपक्षीय गठबंधन को यूएस-जापान संधि के आधार पर एक रणनीतिक रक्षा समझौते में सहिताबद्ध करेगा, जिसमें पेंटागन को हमले की स्थिति में किंगडम की सहायता के लिए आने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। अमेरिका रियाद को खुद की रक्षा के लिए साधन भी प्रदान करेगा जिसमें अत्याधुनिक थ-35 स्टील्थ फाइटर शामिल होंगे। अधिक आश्चर्यजनक रूप से, वाशिंगटन, जो एक अप्रसार हॉक है, सऊदी अरब को शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु तकनीक प्रदान करने के लिए सहमत है। क्षेत्रीय स्तर पर, रियाद गाजा में युद्ध विराम और इजरायल-फिलिस्तीन समस्या के लिए दो-राज्य समाधान की दिशा में कुछ कदम चाहता है। रियाद की अधिकतम मांगों के लिए एक प्रतिफल के रूप में, वाशिंगटन ने कथित तौर पर अपनी खुद की एक चुनौतीपूर्ण इच्छा सूची सामने रखी है। यह चाहता है कि रियाद इजरायल को मान्यता दे और उसके साथ पूर्ण सामान्य राजनयिक संबंध हों। वह यह भी चाहता है कि सऊदी अरब अपनी विदेश नीति को भी सुरक्षित रखे ताकि वह वाशिंगटन के प्रतिद्वंद्वियों, विशेषकर बीजिंग और मास्को के बहुत करीब न जाए।

हालांकि, प्रारंभिक एसएए के सटीक आर्थिक आधार ज्ञात नहीं हैं, लेकिन वे काफी ठोस होने की संभावना है। हालांकि अमेरिका अब सऊदी तेल आपूर्ति पर निर्भर नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष वैश्विक बाजार में अमेरिका की सस्ती ऊर्जा की जरूरत और सऊदी की उच्च तेल राजस्व की चाहत के बीच संतुलन बनाने के लिए अपने लंबे समय से चले आ रहे समन्वय को छोड़ने की संभावना नहीं रखते हैं। एसएए यह सुनिश्चित करने की संभावना है कि एमबीएस के विजन 2030 के तहत परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा अमेरिकी कंपनियों को मिले।

जाहिर तौर पर दिसंबर 2022 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तीन शिखर बैठकों के साथ रियाद की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा ने वाशिंगटन को सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को फिर से सुधारने के लिए मजबूर किया। धीरे-धीरे, "सऊदी अरब को खोने" से बचने के लिए एक अमेरिकी कूटनीतिक जवाबी हमला आकार लेने लगा। अमेरिकी रणनीतिकारों के लिए, तेल-से-सुरक्षा

प्रतिमान में गिरावट के बावजूद, सऊदी अरब ने अपना बहुत महत्व बनाए रखा है। इस्लाम के दो पवित्र तीर्थस्थलों के संरक्षक के रूप में, किंगडम उम्माह, दुनिया भर के 1.4 बिलियन मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक रहा है। इसलिए, अगर सऊदी अरब इजरायल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता देने वाला पाँचवाँ अब्राहम समझौता अरब राज्य बनने के लिए सहमत होता है, तो यह न केवल पश्चिम एशिया को भू-राजनीतिक रूप से फिर से आकार दे सकता है, बल्कि इस्लामी दुनिया के अधिकांश हिस्सों को रियाद के नेतृत्व का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सकता है। दूसरा, सऊदी अरब अरब और इस्लामी दुनिया दोनों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और एक महत्वाकांक्षी विजन 2030 ने बहुत ही आकर्षक विकल्प पेश किए हैं। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने एक दशक के कार्यकाल के दौरान, एमबीएस ने न केवल सत्ता को मजबूत किया है, बल्कि साहसिक और अक्सर विवादास्पद सुधार भी किए हैं। अगर कोई बड़ा सौदा लागू किया जाना है, तो युवा और गतिशील एमबीएस इसे पूरा करने के लिए सही व्यक्ति होंगे।

### बाधाएं:

एसएए परियोजना को साकार होने के रास्ते में दो कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले, पिछले दशक में द्विपक्षीय विश्वास की कमी में वृद्धि देखी गई है। 1990-91 में, अमेरिका ने सऊदी अरब को धमकाने के लिए कुवैत से सद्दाम हुसैन की सेना को बाहर निकालने के लिए सेना तैनात की थी। हालाँकि, जब 2019 में अबकैक और खुरैस में सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल प्रसंस्करण सुविधा पर हमला किया गया, तो अमेरिका ने व्यावहारिक रूप से कुछ नहीं किया। इसके अलावा, अमेरिका ने यमन युद्ध के दौरान कुछ हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, उनके संभावित दुरुपयोग का हवाला देते हुए। अमेरिका ने सामान्य रूप से ईरान के प्रति द्विपक्षीय रवैया अपनाया और विशेष रूप से परमाणु समझौते (संयुक्त व्यापक कार्य योजना) पर हस्ताक्षर करना भी अमेरिका की अविश्वसनीयता का संकेत माना। दूसरी ओर, द्विपक्षीय तेल आधार में गिरावट ने कई अमेरिकी राजनेताओं और राय निर्माताओं को सऊदी अरब की आलोचना करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो बदले में, पिछले दशक में चीन और रूस के करीब चले गए और यहां तक कि ईरान के साथ सुलह भी कर ली। बीजिंग रियाद का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया और श्री शी ने रियाद का दौरा किया। सऊदी अरब वैश्विक कच्चे तेल बाजार को चलाने के लिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक+) के तहत रूस के साथ सहयोग कर रहा है।

एसएए के सामने दूसरी बड़ी बाधा गाजा में चल रहा संघर्ष है, जिसने रियाद के लिए इजरायल के साथ किसी भी तरह के समझौते पर सहमत होना राजनीतिक रूप से अनुचित बना दिया है। यह बिडेन प्रशासन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एसएए को अमेरिकी सीनेट से दो-तिहाई की मंजूरी की आवश्यकता होगी जो केवल रियाद-तेल अबीव के बीच तनाव कम करने के बाद ही संभव है। लेकिन अगर इस दिशा में कोई प्रगति करनी है, तो फिलिस्तीनी अरबों का बेतहाशा खून-खराबा और गाजा में तबाही को रोकना होगा और इजरायल-फिलिस्तीन समस्या के लिए दो-राज्य समाधान को फिर से सामने लाना होगा। हालाँकि, इस संघर्ष को समाप्त करने और क्षेत्र में सामान्य स्थिति की ओर बढ़ने के लिए अमेरिका के लगातार प्रयास अब तक असफल रहे हैं। इस बीच, नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की ओर घड़ी तेजी से बढ़ रही है, जब डोनाल्ड ट्रंप का सामना श्री बिडेन से होगा।

संयोग से, हाल की कई क्षेत्रीय घटनाओं को 11 के चश्मे से देखा जा सकता है: कुछ विश्लेषकों का तो यह भी मानना है कि 7 अक्टूबर को हमला द्वारा इजरायल पर किया गया आश्चर्यजनक हमला 11 को रोकने के लिए था। अन्य संकेतों में शामिल हैं टट्टे में शामिल होने में सऊदी की अनिच्छा, पिछले महीने चीन-अरब फोरम में पूर्व प्रतिबद्धता के बावजूद डई का न जाना, यूक्रेन शांति सम्मेलन में सऊदी विदेश मंत्री की भागीदारी, श्री बिडेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से गाजा शांति योजना का अनावरण और उनके प्रशासन द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का संचालन, राफा पर इजरायली हमले के प्रति अमेरिका की बढ़ती हुई तीखी अस्वीकृति, इजरायली युद्ध कैबिनेट में दरार, कट्टरपंथी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए रिपब्लिकन द्वारा प्रेरित निमंत्रण, इजरायल-हिजबुल्लाह संघर्ष का खतरा और इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का यह बयान कि गाजा युद्ध 2024 के अंत तक चल सकता है।

एसएए की तलाश एक अप्रतिरोध्य शक्ति और एक अचल वस्तु के बीच एक समयबद्ध प्रतियोगिता बन गई है। हम संभावित परिदृश्यों के संभावित प्रभाव के बारे में केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। यदि एक पूर्ण प्रारूपित एसएए पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो यह खाड़ी और पश्चिम एशिया के अधिकांश भाग पर एकध्रुवीयता (पैक्स अमेरिकाना) को फिर से लागू कर देगा। पश्चिम समर्थक शासनों को अधिक आत्मविश्वास मिलेगा और फिलिस्तीनी मुद्दे को आसानी से दफना दिया जाएगा। यदि एसएए की तलाश विफल हो जाती है, तो क्षेत्र में उथल-पुथल रहेगी और ईरान द्वारा बढ़ावा दिए जाने वाले गैर-राज्य अभिनेता क्षेत्रीय संतुलन को बाधित करते रहेंगे। क्षेत्र बाहरी शक्तियों के लिए शतरंज की बिसात बना रहेगा। यह भी संभावना है कि यदि गाजा शांति इतनी दूर तक आने के बाद भी मायावी बनी रहती है, तो रियाद और वाशिंगटन अनिच्छा से एक छोटे से टुकड़े-टुकड़े समझौते पर सहमत हो सकते हैं, जिसमें अन्य मित्र देशों को शामिल किया जा सकता है।

## भारत का दांव:

भारत, जो इस क्षेत्र का एक बड़ा पड़ोसी है और जिसकी इस क्षेत्र में अच्छी-खासी हिस्सेदारी है, को उभरते हुए ग्रैंड बार्गेन पर ध्यान से नजर रखने की जरूरत है। एसएए भारत के समग्र हित में होगा क्योंकि इससे क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ेगी, आर्थिक अवसर पैदा होंगे, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे को बढ़ावा मिलेगा और अमेरिका को अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति का और अधिक सख्ती से पालन करने के लिए स्वतंत्र किया जा सकेगा। साथ ही, भारत को कैप डेविड में इजरायल और सऊदी नेताओं के हाथ मिलाने की तीसरी प्रतिष्ठित छवि का इंतजार किए बिना अपनी खुद की “एक्ट वेस्ट” नीति को आगे बढ़ाने की जरूरत है।

### प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

**प्रश्न:** अमेरिका और सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. ये संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट और सऊदी अरब के राजा अब्दुल अजीज अल-सऊद के समय से शुरू हुए थे।
2. वर्तमान में दोनों देश रणनीतिक गठबंधन समझौता के लिए कार्यरत हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1                      (b) केवल 2  
(c) 1 और 2 दोनों            (d) न तो 1 न ही 2

**Que. Consider the following statements in the context of bilateral relations between America and Saudi Arabia:**

1. These relations started from the time of American President Franklin D. Roosevelt and Saudi Arabia's King Abdul Aziz Al-Saud.
2. Currently both the countries are working for a strategic alliance agreement.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) Only 1                      (b) Only 2  
(c) Both 1 and 2              (d) Neither 1 nor 2

**उत्तर : C**

### मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

**प्रश्न:** अमेरिका और सऊदी अरब रणनीतिक गठबंधन समझौता वर्तमान परिस्थितियों में क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के हितों के संदर्भ में भी इसकी चर्चा कीजिए।

**उत्तर का दृष्टिकोण :**

- उत्तर के पहले भाग में अमेरिका और सऊदी अरब रणनीतिक गठबंधन समझौता की चर्चा कीजिए।
- दूसरे भाग में इस रणनीतिक गठबंधन समझौता के महत्व और इसकी भारत के हितों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
- अंत में अपने सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

**नोट :** अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।